भावनात्मक राजनीति के दौर में जनता के मुद्दे

- संजीव श्रीवास्तव

चुनाव के वक्त - हरेक राजनीतिक दल का वादा और दावा होता है, 'उसे सत्ता में आने का अवसर दिया गया तो 'सुशासन' उसकी सरकार का पहला मूलमंत्र होगा।' सत्ता मिल जाने के बाद सुशासन देने का वादा और दावा अक्सर 'हवा' हो जाता है अथवा बहुत पीछे की पायदान पर खिसक जाता है। सत्ता हासिल करने वाला दल 'सुशासन' की बजाय अगले चुनावों की चिंता में जुटा ज्यादा नजर आने लगता है। हाल के दिल्ली चुनाव के नतीजों ने साबित किया है कि चुनाव केवल राजनीतिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि जनता से जुड़े असली मुद्दों पर लड़े और जीते जा सकते हैं।

कहने को तो केजरीवाल की सरकार में - लोकलुभावन फैसले हुए, जिसमें जनता को सीधा फायदा पहुंचा। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि - सरकारों का असल काम, आम जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुफ्त एवं त्वरित गति से देने का है। केजरीवाल ने इन मुद्दों को अपनी सरकार का एजेंडा बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जनादेश को यह कहकर कमतर साबित करने की कोशिश की कि जनता ने अपने वोट मुफ्तखोरी के चक्कर में बेच दिए। लेकिन सच बात यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए - उससे सरकारें अब बच नहीं सकेंगी।

मध्यप्रदेश में भी एक साल पुरानी कांग्रेस की सरकार इसी दिशा में कुछ कदम उठाती दिखलाई पड़ रही है, ऐसे निर्णयों में केजरीवाल सरकार के फैसले की सीधी-सीधी नकल बिजली के मामले में की गई प्रतीत हुई। जिस तरह से मध्यप्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में सीधा फायदा मिला है, उससे इस बात की आहट मिल रही है कि कमलनाथ सरकार भी केजरीवाल के नक्शे कदम पर है।

भावनात्मक राजनीति के दौर में जब हिंदू-मुसलमान और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक मुद्दे - राज्य के चुनाव में बनने लगे, तब ऐसी दशा में केजरीवाल की राजनीति कहीं नए राजनीतिक सोच की तरफ इशारा तो नहीं कर रही।

अगर इशारा इस तरफ है - तो मध्यप्रदेश सरकार के फैसले यही संकेत देते हैं कि कमलनाथ जैसे अनुभवी राजनेता ने इसे समझने में ज्यादा देर नहीं की है।

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार का समूचा फोकस चुनावी वचन पत्र को निभाने पर है। मुख्यमंत्री पद संभालने के चंद घंटों में किसानों की कर्जमाफी के फैसले को लेकर भले ही विरोधी दलों ने आवाज उठाई हो, लेकिन किसान संतुष्ट नजर आये हैं। अन्नदाता सड़कों पर नहीं, खेत में ही जुटा नजर आ रहा है। '100 रूपये में 100 यूनिट' बिजली महज गरीबों के लिए नहीं हर वर्ग के लिए राहत लेकर आयी है।

मध्यप्रदेश सरकार का 'विजन-टू-डिलिवरी' नजरिया, जनता-जनार्दन के लिए बड़ी सौगात साबित हो रहा है। इंदौर में आरंभ की गई 'द्वार प्रदाय सेवा' - बेहद सफल नवाचार बनकर सामने आयी है। सूबे की व्यावसायिक नगरी के मेहूल बसंल और कैलाश ऐरन इस नवाचार से गदगद नजर आये। ऑनलाइन आवेदन के कुछ ही घंटों बाद मेहूल को मूल निवासी प्रमाण पत्र घर बैठे डिलेवर हो गया। ये और ऐसे दस्तावेजों के लिए आमजन को कलेक्टोरेट और बाबुओं के चक्कर काटने तथा रिश्वतखोरी से मुक्ति वास्तव में गुड गवर्नेंस का नया स्वरूप है। इंदौर का यह नवाचार अब भोपाल में भी आरंभ होने जा रहा है। भोपाल के बाद राज्य के अन्य शहरों में इसे अपनाया जाना तय है।

मध्यप्रदेश को माफिया मुक्त बनाये जाने को लेकर छेड़े गये अभियान ने भी लोगों को भरपूर राहत प्रदान की है। छोटा हो या बड़ा, आम हो अथवा खास - माफिया की नकेल कसने में कोई कोर कसर - मध्यप्रदेश में छोड़ी नहीं जा रही है। गरीब और मजबूर लोगों का खून चूसने वाले सूदखोरों से लेकर सहकारिता माफिया तक त्राहिमाम कर रहा है। अपने घर का सपना संजोकर एक अदद भूखंड और घर खरीदी के लिए जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाने वालों का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है।

निवेश के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। इंदौर में अक्टूबर में हुए 'मेग्निफिसेंट एमपी समिट' के परिणाम सामने आने लगे हैं। धार जिले के पीथमपुर में विदेशी निवेशकों द्वारा तेज गति से कदम बढ़ाना इस बात को द्योतक है कि मध्यप्रदेश निवेश की कथित सफलता रूपी आडंबर एमओयू से ऊपर उठ चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में निवेशक न केवल आये बल्कि कई नये उद्योगों में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है।

ऐसी ब्रांडिंग पहली बार

मध्यप्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के प्रयासों ने भी तरक्की की नई उम्मीदें जगाई हैं। मुख्यमंत्री श्री नाथ 'आईफा अवार्ड' सरीखा आयोजन मध्यप्रदेश लेकर आये हैं। अगले महीने भोपाल और इंदौर में होने वाली इस आयोजन की तैयारियां चरम पर हैं। बेशक - यह आयोजन मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलायेगा।

मध्यप्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। तमाम संसाधन यहां हैं। नैसर्गिक सुंदरता से आच्छादित हमारे राज्य में, मोटी कमाई वाले सिनेमा क्षेत्र का रूख़ पहले भी रहा है। पहले यह छिटपुट था। ऐसा मान सकते हैं कि आईफा के बाद इस क्षेत्र में नये रास्ते खुलेंगे। इस क्षेत्र से मध्यप्रदेश में बड़े निवेश की संभावनाओं के अलावा ज्यादा रोजगार के अवसर भी बढ़ना तय दिखलाई पड़ रहे हैं।

अंत में - कमलनाथ सरकार यदि किसी मोर्चे पर 'फैल' दिखलाई पड़ती है तो वह है, मध्यप्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार (दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी शामिल कर सकते हैं) के सामान 'धुंआधार प्रचार' मामले में। धुंआधार प्रचार की बात आने पर मीडिया वाले चाहें जो सोचें, या लिखें - मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का नजरिया इस दिशा में पूरी तरह स्पष्ट है। जनता से जुड़े बड़े से बड़े फैसलों पर भी धुंआधार प्रचार और प्रसार में दिलचस्पी ना रखने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ हर अवसर पर कहते हैं - 'जनता-जनार्दन, सब जानती है।' बहुत साफ है - मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात को भली-भांति जानते हैं कि प्रचार नहीं - काम करने और राहत देने से, जनता में - सरकार की वास्तविक साख और धाक बनती है। (प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।